SHRI KRISHAN DATT SULTANPURI: Q. No. 760.

MR. SPEAKER: This is your monopoly. Monopoly procurement!

RAO BIRENDRA SINGH: I am getting the advantage of the Speaker being a farmer!

राज्यों में सेब का उत्पादन

*760. श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी :

क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981–82 में सेब का उत्पादन कितना हुआ ;

(ख) उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य देने के बारे में क्या कार्यवाही की गई ;

(ग) वर्ष 1981–82 के दौरान किन देशों को सेव का निर्यात किया गया और विदेशों में सेव की किस किस्म की अधिक मांग थी ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन राज्यों में जहां सेव का अधिक उत्पादन होता है 'वोडका' बनाने का है ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH): (a) The estimated production of apple in 1981-82 is about 9.00 lakh tonnes.

(b) A statement is being laid on the Table of the House.

(c) Apples have been mainly exported to Bangla Desh, Saudi Arabia and Sri Lanka. The variety exported is mainly Red Delicious and its strains.

(d) Vodka is not prepared from apples and hence the question does not arise.

Statement

Several steps have been taken to ensure better prices for the producers. Some of the important steps are as follows:

(1) The creation of separate Departments of Horticulture in the three most important apple growing States of Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh (Hills). Besides creation of a separate Directorate of Planning and Marketing in Jammu & Kashmir.

(2) Creation of Horticulture Produce Marketing and Processing Corporations for apples in Jammu & Kashmir and Himachal Pradesh.

(3) Sanction of World Bank assisted project with an investment of about Rs. 24.22 crores in Jammu & Kashmir and Rs. 16.31 crores in Himachal Pradesh for the creation of an efficient marketing and processing infrastructure for apples.

(4) Apple marketing operations by the National Agriculture Cooperative Marketing Federation (NAFED), Hiachal Pradesh Horticulture Produce Marketing and Processing Corporation (HPMC) and Jammu & Kashmir Horticulture Produce Marketing and Processing Corporation (J&K HPMC).

(5) Fixing of remunerative prices of Rs. 85/- per quintal at the road and Rs. 105/- at processing factory for inferior grade apples in Himachal Pradesh.

श्री कृष्णदत्त सुलतानपुरी : मैं आप का ध्यान इस तरफ् दिलाना चाहता हूं, ।

अध्यक्ष महोदय : सवाल पूछिये, ध्यान मत दिलाइये ।

श्री कृष्णदत्त सुलतानपुरी : हिमाचल प्रदेश में अधिक मात्रा में सेव होता है, मैंने क्वैश्चन किया था हिमाचल प्रदेश के बारे में, राव साहब ने 81–82 में कुल कितना सेव हुआ वह बताया है । उसके

साथ-साथ मैंने यह भी पूछा कि उत्पादक को क्या लाभ मिला है ?

हिमाचल प्रदेश में दूरदराज के इलाके में जहां सेव पैदा होता है, उसको सड़क तक लाने में बहुत भारी कैरिज देना पड़ता है। रोड साइड पर सेव जब आता है तो उसके दाम 85 रुपये क्विंटल घटिया सेव के मंत्री जी ने अपने विवरण में बताये हैं, लेकिन अच्छे किस्म का सेव जो आजादपुर और मार्कटों में आता है हिमाचल और जम्मू काश्मीर से जो कि पहाड़ी ऐरिया हैं, उसके लिये आपने क्या प्रबन्ध किया है कि उनको भी अच्छे दाम मिलें ?

सेव की पेटी जो बनाते हैं, उसमें फारेस्ट की बढ़िया लकड़ी काटी जाती है। हमारे हिमाचल प्रदेश में भी 16,17 करोड़ की लकड़ी काटी गई है इस साल में। क्या आपके विचार में यह बात है कि सेव की पेटियां सरकारी तौर पर तैयार कर के किसानों को दी जायें सस्ते दामों पर ? किसान को जो सेव की पेटी का भाव और कैरिज का खर्च देना पड़ता है, क्या उसका कोई उचित प्रबन्ध करना चाहते हैं या नहीं ?

राव वीरेंद्र सिंह : हिमाचल के लिये मार्केटिंग और प्रासेसिंग की तरफ खास ध्यान दिया गया है। वहां 16 करोड़ रुपये का एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है जिसमें कोल्ड स्टोरेज लगाये गये हैं और प्रासेसिंग के लिये प्लान्ट्स लगाये गये हैं। हिमाचल में अब 6,7 परसैंट के करीब सेव प्रासेस हो जाता है। प्रासेसिंग के जरिये सेव का इस्तेमाल करने की काफी तादाद बढ़ी है। इसी तरह से जम्मू और काश्मीर में भी 24 करोड़ का मार्केटिंग और प्रासेसिंग के लिये वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके जरिये ज्यों-ज्यों प्रासेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, सेव की अच्छी कीमत किसानों को मिलेगी। मार्केटिंग का बन्दोबस्त करने के लिये ये प्रोजेक्टस हैं।

पेटियां सरकारी तौर पर सप्लाई करने का इनका सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय : इंटरमीडियरी बहुत खाता है बीच में।

श्री कृष्णदत्त सुलतानपुरी : मंत्री जी ने जैसा बताया कि 16 करोड़ रुपये से ऊपर राशि कोल्ड स्टोरेज और प्रासेसिंग के लिये खर्च की है और उन्होंने 105 रुपये का भाव घटिया सेव आ फैक्टरी का बताया है, लेकिन जो अच्छे सेव हमारे हिमाचल प्रदेश और काश्मीर व दूसरे इलाकों से आते हैं, उनका भाव न इन्होंने निर्धारित किया है और न ही कुछ बताया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि विदेश के लिये कितना सेब इन्होंने यहां से भेजा और उसका क्या दाम किस किस राज्य सरकार को मिला।

हिमाचल प्रदेश में जो आपने बताया कि सहकारी संस्था और दूसरे जो प्रोजेक्ट बनाये हैं, उसमें 85 रुपये क्विंटल के भाव सेव खरीदा तो अभी बहुत से किसानों को उनका पैसा नहीं मिला है, वह कब तक उनको मिल जायेगा, इस बारे में भी बतायें ?

राव वीरेन्द्र सिंह : 105 रुपये का भाव हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रोक्योरमेंट के लिये तय किया था और 30,800 टन के करीब सेव पिछले सीजन में इन्फीरियर क्वालिटी का खरीदा प्रासेसिंग के लिये और जूस कंसेंट्रेट बनाने के लिये। सैंट्रल गवर्नमेंट ने न सेव का भाव तय किया है और न सैंट्रल गवर्नमेंट इस मामले में पड़ना चाहती है। स्टेट गवर्नमेंट की हम इमदाद कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के प्राजेक्ट चल रहे हैं। जैसा मैंने अर्ज किया

कि ज्यों ज्यों किसानों को इसका फायदा पहुंचेगा, इसका भाव बढ़ जायेगा।

DR. KARAN SINGH: In part (d) of the question, my colleague from Himachal Pradesh has obviously mixed up 'Vodka' and 'cider'. What he really meant was whether Government proposed to prepare cider. Apple cider is highly nutritious; it has a very low alcohol-content and is a very good drink. Would the Minister tell the House whether they will encourage the production and export of cider which can earn crores of rupees and is a much better drink than the sort of drink which people are using in this country?

RAO BIRENDRA SINGH: Cider production is also being taken up in the processing projects.

DR. KARAN SINGH: Are you encouraging it?

RAO BIRENDDRA SINGH: A lot of it is being produced already. if there are any other proposals, they will be considered.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : इस बारे में मुझे व्यक्तिरूप से कुछ जानकारी है, क्योंकि मैं एक सेब का व्यापारी हूं। तीन साल पहले मैं कुल्लू गया था और वहां पर मैंने 10,000 क्विंटल सेब खरीदा था, जिसकी कीमत 80 पैसे और 1 रुपया के० जी० थी। लेकिन उसकी वारणसी ला कर बेचने में हमें करीब करीब 3.50 रुपये के० जी० की लागत पड़ गई। हमें काफी रुपया बिचौलियों को देना पड़ा। इसके इलावा वहां से यहां सेब लाने के लिये सरकार की ओर से कोई उचित व्यवस्था नहीं है उस सीजन में, जबकि सेब अधिक होता है। क्या सरकार की ओर से वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था होगी और उन बिचौलियों पर नियंत्रण किया जाएगा, जो काफ़ी रुपया ले लेते हैं, जिससे न व्यापारियों को और न किसानों को लाभ होता है। इसके अतिरिक्त वहां पर किसानों को उचित मूल्य मिलना चाहिए, जोकि आज नहीं मिल पाता है। सेब को लाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं भी नहीं हैं। क्या सरकार इसके लिए कोई व्यवस्था करेगी।

राव वीरेन्द्र सिंह : हम सोच रहे हैं कि इन व्यापारियों की धांधली को ख़त्म करने के लिए और क्या उपाय किए जा सकते हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आपने जो दलाल बीच में छोड़ रखे हैं, उनकी धांधली को ख़त्म करने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

राव वीरेन्द्र सिंह : हम सोच रहे हैं कि सैंट्रल लेबल पर एक कार्पोरेशन बनाएं, जिससे मार्केटिंग इम्परूव हो और प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा दिया जाए।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

Idle Deep Sea fishing Trawlers at Vizag Port

†758. SHRI G. M. BANATWALLA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether imported deep-sea going trawlers are lying idle at Vizag port;

(b) if so, the number of such trawlers and since when they are lying idle;

(c) the reasons for their laying idle;

(d) whether these trawlers suffer from operational deficiencies due to factors like faulty designs and unsuitability to Indian conditions;

(e) if so, the circumstances leading to their import; and